

# सांख्याप्रकाश

आरएनआई 22296/71 ■ डाक पंजीयन मप्र/भोपाल/125/12-14



पीएम मोदी, गृहमंत्री शाह, भाजपा अध्यक्ष नड़ा सहित कई मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थित में शपथ समारोह

## मोहन यादव ने ली मुख्यमंत्री की शपथ जगदीश देवड़ा-राजेन्द्र शुक्ल बने उप मुख्यमंत्री

**भोपाल।** मध्यप्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। वे मप्र के 20वें मुख्यमंत्री हैं। समारोह भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। जगदीश देवड़ा और राजेन्द्र शुक्ल ने डिटी सीएम के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल नंगवार्ड पटेल ने सभी को शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड़ा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, निवृत्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर एवं प्रह्लाद सिंह पटेल समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री इस समारोह में शामिल हुए। फिलहाल, कोई और विधायक ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली है। कार्यक्रम 10 मिनट का रहा। शपथ लेने से पहले मोहन यादव ने कहा, सभी को साथ लेकर चलूंगा और सुशासन स्थिति करूंगा। शपथ समारोह में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पूर्व राज्यपाल कपान शिंह सोलंकी, प्रदेश के गृहमंत्री डा. नरेतम मिश्रा सहित अनेक नेता भौजूद रहे।

उपाध्याय एवं  
मुख्यमंत्री की प्रतिमाओं पर  
माल्यार्पण किया

प्रदेश के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव एवं भाजपा जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने बुधवार को प्रदेश कार्यालय में पै. दीनदयाल उर्द्धवाय जी एवं डॉ. श्यामासाह मुख्यमंत्री की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। मोहन यादव को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का करीबी माना जाता है और उन्हें शीर्ष पद के दावेदार के रूप में नहीं देखा जा सकता। वह अन्य पिछ्या वर्ष (अबेसी) समूह से आते हैं, जिनकी संख्या राज्य की जनसंख्या में एक बड़ा संबंध संस्थान से अधिक है। सम्भालने का अधिक होने के बाद यादव ने राज्यपाल मुख्यमंत्री पटेल से मूलाकात की और अगली सकार बनाने का दावा पेश किया।

दिल्ली से तय होने वाले निर्वाचक दल के द्वारा भोपाल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्रियों की शपथ के बाद अब मोहन मंत्रिमंडल के चेहरों की तलाश शुरू हो गई है। खबर है कि कैबिनेट के चेहरों का चयन दिल्ली हाईकोर्ट मान से ही होता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश संसदन और दिल्ली हाईकोर्ट मान से सलाह मिश्रित करेंगे। मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालने के बाद अब यादव को नाम तय करेंगे। लेकिन इससे पहले मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जल्द ही दिल्ली जाएंगे और मंत्रियों के नाम को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड़ा से सलाह-मिश्रित वर्ष करेंगे, ताकि जारी की जाए। मुख्यमंत्रिमंडल में नए चेहरों की अधिकता तब जो मिल सकती है, इसमें पहली और दूसरी बार के विधायक भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही अनुभवी नेताओं के साथ पुराने चेहरे भी मोहन कैबिनेट में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जल्द ही दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं।

### शिवराज बोले-जस की

#### तस धर दीनी चढ़ारिया...

एनएमुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने शाम चार बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। इसके बाद पांच बजे कैबिनेट बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में अधिकारियों से औपचारिक परिचय होता है। मुख्यमंत्री आचार सहित के कारण बड़े हुए आवायक कार्य पिर से शुरू करने को कह सकते हैं।



नवनियुक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव के बैठक का शपथ समारोह अपने घर पर बैठकर देखा।



समारोह में तीन मंच बने, एक पर साधु-संत बैठे शपथ ग्रहण समारोह में तीन मंच बना रहा। मुख्य मंच के बीचोंबीच तीन कुर्मियां रखी रही थीं। बीच वाली कुर्मी पर राज्यपाल मंगू भाऊ पटेल बैठे। उनके दायें और पीएम मोदी और बाईं तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव बैठे। मोहन यादव पीएम की कुर्मी के दायें तरफ खड़े थे तो मोदी ने हाथ पकड़कर उनसे बैठने को कहा। तीन मंचों में बाईं तरफ के मंच पर कारीब एक दूसरा साधु-संत बैठे थे। दायें तरफ के मंच पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड़ा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बालाल संतोष, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, निवृत्तमान मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री बैठे थे। इन्होंने कुर्मियों पर नरेंद्र सिंह नाथ, शिवराज सिंह चौहान, प्रह्लाद पटेल और राकेश सिंह भी बैठे थे। सांसद से विधायक बनी रीत पाठक आमजन के बीच बैठी थीं।

## सुरक्षा में बड़ी खुक्का: लोकसभा की दर्शक दीर्घा से कूदे दो शख्स, सदन में उठता दिखा धुआं...

नई दिल्ली। लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी खुक्का का मामला सामने आया है। संसद के शीतकालीन सत्र में 10वें दिन की कार्यवाही के दौरान जब सांसद शून्यकाल में लोकमहल के अविलम्बनीय मुद्दों पर अपनी बातें रख रहे थे, इसी दौरान दर्शक दीर्घा से दो शख्स बारी-बारी से सदन में कूदे। अफरा-तफरी मचने के कारण सदन की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित करनी पड़ी। सदन में पीठासीन गोदान गोदान राज्यपाल ने कार्यवाही को स्थगित करने की घोषणा की। तोपें बरी 1.01 मिनट पर यह घटना हुई।

मीडिया में आई खबरों के अनुसार दो शख्स जब गैलरी से कूदे उसी समय सदन में धुआं भी उठा। अफरा-तफरी मचने के बाद सुरक्षाकर्मियों ने दोनों लोगों को पकड़ा। सांसदों ने बताया



कि सबसे पहले खुद सांसदों ने दोनों लोगों को पकड़ा, उनकी पिटाई की गई। इसके बाद दोनों को सदन में बौद्धि सुरक्षाकर्मियों के हवाले कर दिया गया। युवक अपने जूते में बिल्कुल स्मोक बल लाया था। उन्हें पीले रंग का धुआं छोड़ा। मैसूरु के सांसद प्रताप सिंह नाथ ने जब दोनों लोगों को पकड़ा तो उन्हें बैठाकर युवक संसद भवन तक पहुंचा था।



आगे युवक का नाम सापर है। जबकि एक महिला और एक युवक ने संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया। युवक का नाम अमोल शिंदे है जो महाराष्ट्र के रहने वाला है। युवती की बहाना नीतम के रूप में कोई नहीं है जो हरियाणा की रहने वाली है। दोनों से पूछताछ जारी है। खबर बात ये है कि आज ही संसद पर आत्मीयों ने आज ही पुराने संसद भवन पर आत्मीय हमता किया था।







सम्पादकीय

## नई भारतीय न्याय संहिता और आतंकवाद



Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023

मगलवार का सदस्य पश्चात् एक गण नए अपाराधिक कानूनों में पहली बार आतंकवाद यानी टेरर एक्ट के लिए अलग से प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि आगर कोई शख्स भारत की अधिक स्थिताओं और सुरक्षा को खतरा पैदा करता है और इसके लिए जाली नोट या सिक्के समग्र करता है, तबना या इनका प्रसार करता है तो वह आतंकवादी करतून माना जाएगा।

भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 यानि बीएनएस के संशोधित कानून में आतंकवाद के कृत्यों से निपटने वाली धारा 113 में संशोधन किया गया है। इसका उद्देश्य बीएनएस को यूएपीए के प्रावधानों के अनुरूप लाना है। इसमें आतंकवादी कृत्य की परिभाषा में बदलाव किया गया है, जिसमें देश की अधिक सुरक्षा और मौद्रिक स्थिता पर हमले शामिल हैं। हालांकि, आम जनता को धमकाने या सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने को अब आतंकवादी कृत्य नहीं माना जाएगा।

भारतीय न्याय संहिता विधेयक की धारा 113(1) में प्रावधान है कि आगर कोई व्यक्ति ऐसी मंशा या हरकत करता है, जिससे देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को नुकसान या खतरा पैदा होता है या आतंकी घटना की मंशा रखता है, आतंकी हमले करता है, इसके लिए बम, हथियार, केमिकल, बायोलॉजिकल और जहर आदि का इस्तेमाल करता है, जिससे जान-माल का नुकसान हो तो ऐसे मामले में दोषी शख्स को उप्रेक्षा या फांसी की सजा हो सकती है।

भारतीय न्याय संहिता विधेयक की धारा 113(5) में कहा गया है कि आगर कोई शख्स भरत की रक्षा परिसंपत्ति को नुकसान पहुंचाता हो या अन्य ताह की सकारा की ऐसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता हो तो वह आतंकवाद यानी टेरर एक्ट माना जाएगा। इसी कानून की धारा 113(बी) में कहा गया— अगर कोई संवैधानिक पद पर बैठे या पब्लिक फंक्शनरी पर हमला करता है या अगवा करता है या ऐसी मंशा रखता है तो ऐसे मामले को भी टेरर एक्ट माना जाएगा। इसमें मौत होने पर उप्रेक्षा और फांसी की सजा का प्रावधान है।

भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक में आतंकवाद की परिभाषा में अब अन्य परिवर्तनों के साथ-साथ अधिक सुरक्षा शब्द भी शामिल है। इस बदलाव में कहा गया है, जो कोई भी भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या अधिक सुरक्षा को धमकी देने या खतरे में डालने की नीयत के साथ या भारत या किसी दूसरे देश में लोगों में या लोगों के किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने की नीयत के साथ कोई कार्य करता है...। भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता विधेयक में विभिन्न आतंकवादी कृत्यों के लिए प्रस्तावित 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक के जुमानिं को हटा दिया गया है। अब जुमानि की राशि अदालतें तय करेंगी। इसना ही नहीं, इससे उपराधन की राशि दिया जाएगा। इससे जिसके परिणामस्वरूप किसी पीड़ितों की मृत्यु हुई है और जिसे उपराधन में शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप किसी पीड़ितों की मृत्यु हुई है और जिसे उपराधन में शामिल है।

मूल बीएनएस विधेयक में आतंकवादी कृत्य करने वाले पर 10 लाख रुपये का जुमाना लगाने का प्रस्ताव था। वही, अन्य मामलों में 5 लाख रुपये का जुमाना लगाने का प्रस्ताव था, जिसमें आतंकवादी साजिश से संबंधित मामले, आतंकवादी संगठन का सदस्य होना, किसी आतंकवादी को शरण देना और आतंकवादी गतिविधियों से अर्जित संपत्ति रखना शामिल है।

इसी तरह मूल विधेयक में सरकारी कर्मचारियों को डारने-धमकाने को शामिल किया गया था। उसमें कहा गया था कि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने या उसे चोट लगाने की आशंका हो या मानने की धमकी देकर सरकारी कर्मी को कोई कार्य करने या करने से रोकने के लिए बंधक बनाया जाए या अपहरण किया जाए तो वह अपराध होगा। नए विधेयक में इन प्रावधानों को आपराधिक जोर-जबर्दस्ती के दम पर किसी सरकारी कर्मी की मृत्यु का करण बनने और किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने, अपहरण करने या बहला-फूसलाकर भगाने और भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी विदेशी सरकार या किसी अंतर्राष्ट्रीय या अंतर सरकारी संगठन को मारने या घायल करने की धमकी देने के रूप में फिर से तैयार किया गया है।

अप्रेटेट बीएनएस बिल के सेक्षन 113 में कही गई बातें यूएपी की धारा 15 से धारा 21 के तथ्यों के ही कीरब है। विधेयक स्पष्ट करता है कि बीएनएस की धारा 111 या यूएपी के लिए बम दर्ज करने का नियंत्रण पुलिस अधीक्षक (एसपी) के पद से नीचे के अधिकारी नहीं लेंगे। सभी प्रकार के आतंकवादी कृत्यों के लिए अधिकतम और न्यूनतम सजा को बरकरार रखते हुए नए बीएनएस बिल में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने और किसी व्यक्ति को आतंकवादी कृत्य के लिए भर्ती करने के लिए जुमाने के साथ कम से कम पांच साल और अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा का अलग से उल्लेख किया गया है।

विधेयक में धारा 73 में बदलाव किए गए हैं, जिससे अदालत की ऐसी कार्यवाही प्रकाशित करना दंडनीय हो जाएगा जिसमें अदालत की अनुमति के बिना बलाकार या इसी तरह के अपराधों के पीड़ितों की पहचान उत्तरांग हो सकती है। धारा 73 में अब कहा गया है, जो कोई भी अदालत की पूर्व अनुमति के बिना धारा 72 में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में अदालत के समक्ष किसी भी कार्यवाही के संबंध में किसी भी मामले को प्रिंट करने एवं जेल की सजा दी जाएगी। इसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है।

अभी ये बदलाव लाये गये हैं, इन्हें लागू भी किया जा रहा है, लेकिन जमीनी तौर पर इसमें काफी किटनाही आयी है। सबसे पहले तो थानों और अदालतों में इसका विस्तृत ब्यौरा पहुंचना होगा। कुल मिलाकर अभी इसमें काफी समय लगेगा। साथ ही कानून के जानकार इसका विश्लेषण भी करेंगे, सामाजिक संगठनों का अपना नजरिया होगा। लेकिन भारतीय न्याय संहिता का नया स्वरूप आ गया है, यही लागू होगा।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक भरत पटेल द्वारा इंडिपेंट प्रेस 11, प्रेस काम्पलेक्स, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल से मुद्रित तथा 226, एमपी नगर जोन-2, भोपाल से प्रकाशित। संपादक — भरत पटेल, प्रबंध सलाहकार — भरती पटेल, संपादकीय सलाहकार — विष्णु कौशिक, सलाहकार संपादक — सिताना पटेल, स्थानीय संपादक — संजय सरकार, एक्ट के लिए प्रियंका दिमेंदार। समस्त न्यायिक कार्यवाहीयों के लिए क्षेत्रीय विधानसभा भोपाल न्यायालय का रेखा। जी. नं. भोपाल दिवी. 48 मप्र। ई-पेट : dspbp16@gmail.com, वेबसाइट : dainiksandhyaprakash.in

## वादों पर इनके लुटा, मतदाता बेचाया

### राकेश दुबे

देश के उपरायपति जगदीप धनखड़ ने बहुत मार्कें की बात कही है कि समाज में जिस तथाकथित मुफ्त उपचार की 'अंगी दीड़' देखने को मिल रही है, उसकी राजनीति खर्च करने संबंधी प्राथमिकताओं को विकास कर देती है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव के परिवेश इसे देखा और समझा जाना चाहिए। इन दिनों गारंटी शब्द इनका लोकप्रिय हो रहा है कि इस बार भाजपा ने तो 'मोदी की गारंटी' नाम का जुमला ही बना लिया है।

सिर्फ भाजपा ने ही नहीं, कंग्रेस ने चार राज्यों में और लेलांगन में भी गारंटीयों की जड़ी लगा दी। इन वार्ताएं में एलपीजी सिलेंडर रिफिल पर भारी सब्सिडी, स्ट्रिंगों को हाथ महीने धनराशी वौगैर-वौगैर शामिल हैं। इस साल मई में हुए कानूनटक विधानसभा के चुनाव में कागिस की मिलाई सफलता के पीछे 'पांच गारंटीयों' की बड़ी भूमिका थी। पार्टी ने तो चुनावी घोषणापत्र में गारंटी योग्यता और लोकप्रिय योग्यता दी थी।

गृह ज्ञाती के तहत 200 यूनिट निश्चुल्क विधेयक, 2023 यानि बीएनएस के विधेयक, 2023 यानि बीएनएस के संशोधित कानून में आतंकवाद के कृत्यों से निपटने वाली धारा 113 में संशोधन किया गया है। इसका उद्देश्य बीएनएस को यूएपीए के प्रावधानों के अनुरूप लाना है। इसमें आतंकवादी कृत्य की विधिएक विधानसभा के चुनाव में कागिस की मिलाई सफलता के पीछे 'पांच गारंटीयों' की बड़ी भूमिका थी। पार्टी ने तो चुनावी घोषणापत्र में गारंटी योग्यता और लोकप्रिय योग्यता दी थी।

गृह ज्ञाती के तहत एक बात कही गयी है कि आगर कोई शख्स भारत की अधिक स्थिताओं और सुरक्षा को खतरा पैदा करता है और इसके लिए जाली नोट या सिक्के समग्र करता है, तबना या इनका प्रसार करता है तो वह आतंकवादी करतून माना जाएगा।

भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 यानि बीएनएस के संशोधित कानून में आतंकवाद के कृत्यों से निपटने वाली धारा 113 में संशोधन किया गया है। इसका उद्देश्य बीएनएस को यूएपीए के प्रावधानों के अनुरूप लाना है। इसमें आतंकवादी कृत्य की विधिएक विधानसभा के चुनाव में कागिस की मिलाई सफलता के पीछे 'पांच गारंटीयों' की बड़ी भूमिका थी। पार्टी ने तो चुनावी घोषणापत्र में गारंटी योग्यता और लोकप्रिय योग्यता दी थी।

गृह ज्ञाती के तहत एक बात कही गयी है कि आगर इस बारे में गारंटी योग्यता और लोकप्रिय योग्यता दी थी।

गृह ज्ञाती के तहत एक बात कही गयी है कि आगर इस बारे में गारंटी योग्यता और लोकप्रिय योग्यता दी थी।

गृह ज्ञाती के तहत एक बात कही गयी है कि आगर इस बारे में गारंटी योग्यता और लोकप्रिय योग्यता दी थी।

गृह ज्ञाती के तहत एक बात कही गयी है कि आगर इस बारे में ग



संसद के दोनों सदनों में शहीदों को श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले को आज 22 साल हो गए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के आज आठवें दिन (13 दिसंबर) की कार्यवाही शुरू होने से फहले पीएम मोदी समेत कई नेताओं और सांसदों ने हमले में शहीद हुए जवानों के श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम मोदी और उपराष्ट्रमंत्री जगदीप धनखड़ ने शहीदों के परिवार से मुलाकात की। संसद भवन के बाहर श्रद्धांजलि स्थल पर पीएम मोदी के साथ गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा स्पीकर औम बिरला, बीजेपी सांसद जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्किएर्जुन खड़गे और सांसद सोनिया गांधी समेत कई नेता मौजूद थे।

इस दौरान पीएम मोदी ने संसद भवन पर हमले में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद पर 13 दिसंबर 2001 को हुए हमलों के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। संसद परिसर में लोकसभा की कार्यालयी में भाग लेने से पहले जम्मू-कश्मीर से निवार्चित वयोवद्ध सांसद फारूक अब्दुल्ला ने सर्विधान के अनुच्छेद 370 से जुड़े एक सवाल पर कहा, भारत के 75 साल के इतिहास में किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नहीं बदला गया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों (ज़.) को राज्य का दर्जा देने की घटनाएं कई बार हुई हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर बीते चार साल से अधिक समय से केंद्र शासित प्रदेश क्यों है? पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल क्यों नहीं किया जा रहा है? सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। बता दें कि इससे पहले भी एक ब्यान में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला केंद्र सरकार के रवैये को लेकर नाराजगी का इजहार कर चुके हैं।

संसद के शीतकालीन सत्र में दूसरे देश में भारतीयों पर कार्यवाई के मुद्दे की गंज भी सुनाई दी। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहते में पूर्व नौसेना कमिटी को मौत की सजा सुनाए जाने के मामले पर चर्चा की मांग की। लोकसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव का गोटिस देते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा पूर्व नौसेनिकों की वर्तमान स्थिति और उन्हें भारत वापस लाने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा की मांग की।



**जनगणना में जानबूझकर देती कर रही सरकार, लोकसभा में चर्चा की मांग**

एक अन्य कांग्रेस सांसद मणिकम टैगेर ने भी लोकसभा महासचिव के पास कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया। उन्होंने जनगणना शुरू करने में केंद्र सरकार की तरफ से असामान्य और जानबूझकर देरी किए जाने का आरोप लगाया। मणिकम टैगेर ने जनगणना के मुद्र पर चर्चा के बाद सरकार को तत्काल जनगणना प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देने की मांग भी की।

# फोटो मीटर रिडिंग में लापरवाही, 18 आउटसोर्स मीटर वाचकों की सेवाएं समाप्त, 127 का वेतन काटा

## मीटर ईडयों पर निगरानी रखने एवं सख्त कार्यवाही के निर्देश

सांघ्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने नव

माह में उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग लापरवाही बरतने के आरोप में सेवा प्रक्रिया कंपनी के माध्यम से कंपनी कार्यक्षेत्र कार्यरत 18 मीटर वाचकों को इय्युटी से पृष्ठ करने के साथ ही 127 मीटर वाचकों का वाचकाटा गया है। इसी प्रकार 78 मीटर वाचकों को कार्य में लापरवाही बरतने के चेतावनी जारी की गई है। कंपनी कार्यक्षेत्र

अंतर्गत भोपाल में 6, ग्वालियर में 5, भिण्ड, अशोक नगर, नर्मदापुरम्, दतिया, शिवपुरी, बैतुल एवं राजगढ़ में 1-1 आउटसोर्स मीटर वाचक को आदेशों की अव्हेलना और मीटर वाचन में गड़बड़ी के आरोप में सेवा से पृथक कर दिया गया है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री गणेश शंकर मिश्रा ने मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि उपभोक्ताओं के परिसर पर एक्युरेसी (शुद्धता) के साथ मीटर वाचन होना चाहिए और मीटर रीडिंग के आधार पर ही उपभोक्ताओं को विद्युत देयक दिए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मीटर वाचकों के

कार्य पर निष्ठा एप के द्वारा निगरानी रखी जाए और जो मीटर वाचक कर्तव्य पालन में लापरवाही बरत रहे हैं, उन्हें सेवा से पृथक किया जाए। प्रबंध संचालक ने कहा कि उपभोक्ता सेवा सर्वोपरि है। उपभोक्ताओं को कंपनी बेहतर से बेहतर सेवाएं देने के लिए कृत संकल्पित है और इसी दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने उपभोक्ताओं को जागरूक रहने के लिए कहा है कि जब उनके परिसर की मीटर रीडिंग होती है तो वे मीटर वाचक द्वारा ली गई रीडिंग और मीटर में दर्ज रीडिंग पर नजर रखें ताकि सही देयक मिल सके। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्रयास है कि बिलिंग संबंधी शिकायतों को

शून्य लेवल पर लाया जाए। कंपनी के प्रबंध सचिव श्री गणेश शंकर मिश्रा ने कहा है कि फोटो मीटर रीडिंग निष्ठा एवं के माध्यम से की जा रही है। दरअसल फोटो मीटर रीडिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं है और मीटर वाचन में अंकित वाचन की फोटो खींचकर सिस्टम में अपलोड की जाती है। मीटर वाचकों पर कड़ी निगरानी और लापरवाही बरतने वाले मीटर वाचकों को सेवा से मुक्त किये जाने की कार्यवाही के कारण उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है कुछ शहरों में क्युआर कोड लगाने के कारण भी फायदा मिला है एवं इससे मीटर वाचन की प्रक्रिया जल्दी संपादित हो रही है।



भोपाल। मध्य प्रदेश की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल पहुंचे। नवनियुक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ पार्टीसंघर्ष से बचने के लिए यादव ने अपने देवता द्वारा दिया।

# नव नियुक्त मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वीकार किया जन-जन का अभिवादन

**विंध्य कोटी और विशाल भवन में जायी रहा बधाईयों का कम**



**भोपाल।** नवनियुक्त मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों, पार्टी के वरिष्ठ सदस्यगण सहित जनानियन्त्रिकाओं, गविन्निमयों और अन्यानियतों द्वारा नए दायित्व के लिए बधाईयों का क्रम जारी रहा। उज्जैन, भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं और जनसामाजिक वैदिकों को दी गई तश्वीचोंमें से एक है।

# एम्स ने सीआरआरटी से बचाई जहर से प्रभावित तीन रोगियों की जान



सांघ्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

एम्स भोपाल में मेडिकल इंटेर्सिव केरर यूनिट (एमआईसीयू) के डॉक्टरों, नर्सों और पैरामर्डिकल स्टाफ की समर्पित टीम ने पिछले महीने में एल्युमीनियम फॉस्फाइड के जहर से प्रभावित पांच में से तीन रोगियों की सफलतापूर्वक जान बचाकर उन्हें नया जीवन प्रदान किया। एल्युमीनियम फॉस्फाइड जैसे घातक जहर से बचना लाग्भग नामुमकिन होता है। एम्स भोपाल ने कर्तीना अम् गीनल फिल्म्स पर्सनें

थेरेपी (सीआरआरटी) के द्वारा इस घातक जहर के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक सफलता प्राप्त की है। एप्स एमआईसीयू के डॉक्टर इस बात पर जोर देते हैं कि में गंभीर मेटाबॉलिक एसिडोसिस था, जिसका पीएच स्तर 7.0 से नीचे था और सीरम लैक्टेट का स्तर 20द्वृश्या/रुकी सीमा में था।

सीआरआरटी को जितनी जल्दी हो सके शुरू करने से एल्यूमिनियम फॉस्फाइड के इलाज में अभृतपूर्व सफलता मिल सकती है। जीवित बचे लोगों में एक 17 वर्षीय महिला, एक 20 वर्षीय पुरुष और एक 44 वर्षीय व्यक्ति शामिल हैं। ये सभी मरीज जहर खाने के 12 घंटे के भीतर एस्स में इलाज के लिए लाये गए थे। इन मरीजों एस्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर (डॉ.) अजय सिंह ने अथक परिश्रम और अटटू प्रयासों के लिए टीम को हार्दिक बधाई दी। डॉ. सिंह ने इस उपलब्धि के महत्व पर जोर देते हुए कहा, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड विकाषकता के इलाज में सफलता हमारी चिकित्सा टीम के मार्गांश और तिष्ठेचनात् का प्रमाण है।





मध्यप्रदेश शासन



नरेन्द्र मोदी  
प्रधानमंत्री

एमपी के  
**मन में मोदी**

जन-जन का  
**आभार**  
आपने चुनी  
ठबल इंजन सरकार

मध्यप्रदेश की  
नवनिर्वाचित सरकार का

**दृष्टि ग्रहण  
समारोह**

13 दिसम्बर, 2023  
पूर्वाह्न 11:30 बजे

मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, भोपाल



डॉ. मोहन यादव  
नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री